**Production of Aman Paddy Crop in West Bengal**

1000. SHRI TRIDIB CHAUDHURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received any estimates of the total production of Aman paddy crop in West Bengal this year (1972-73) and of the expected shortfall in production as compared to production last year (1971-72) and the annual requirements and what are these estimates;

(b) what are the procurement targets set for West Bengal for the Aman crop this year, how far they have been realised through the Food Corporation of India or otherwise; and

(c) how much or what proportion of the Food Corporation of India procurements from West Bengal are earmarked for utilisation within West Bengal in the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) Estimates of the total production of Aman paddy crop in West Bengal this year (1972-73) and of the expected shortfall in production have not yet become available. The Government of West Bengal have estimated their requirements of rice for 1973 as 10 lakh tonnes.

(b) No separate target for procurement of Aman crop has been fixed for West Bengal. Against a target of 3 lakh tonnes of rice fixed for procurement for 1972-73 marketing season in the State, 1.14 lakh tonnes has been procured by the Food Corporation of India upto 19th February, 1973.

(c) Entire procurement made by the Food Corporation of India in West Bengal is meant for utilisation within the State.

---

**12.01 hrs.**

## ALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### REPATRIATION OF PERSONS OF INDIAN ORIGIN FROM SRI LANKA

SHRI HARI SINGH (Khurja): Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"The question of repatriation of about 35,000 persons of Indian origin from Shri Lanka to India this year."

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है, हिन्दी की प्रतिलिपि नहीं है। ऐसी प्रथा है कि स्टेटमेंट की हिन्दी प्रतिलिपि भी मिलती है।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): As the House is aware, the Indo-Ceylon Agreement of 1964 envisaged that India would accept for repatriation 525,000 stateless persons of Indian origin, while Sri Lanka would grant citizenship to 300,000 such persons, in an evenly phased manner over a period of 15 years; this would mean that India would accept repatriation of an average of 35,000 persons per annum and Sri Lanka would grant citizenship to 20,000 persons per annum beginning from the date of the Agreement.

Since various perior arrangements had to be made, implementation of the Agreement has been delayed. Till the 17th February 1973, 84,801 persons have been repatriated to India, while Sri Lanka has granted citizenship to 48,249 persons upto the end of December 1972.

A meeting of officials of the two countries led by their respective Foreign Secretaries was held in Colombo from 14th to 17th February this year to review progress in the implementation of the Agreement. The Agreement was considered in all its aspects, and both sides agreed to take all possible measures to ensure its smooth and full implementation. During the last eight years, the stipulated rate of repatriation of 35,000 on Indian side and the grant of citizenship to 20,000 on Sri Lanka side could not be achieved. Government of India has agreed in principle to accelerate the rate of repatriation in the coming years. The details are being worked out.

श्री हरी सि : अध्यक्ष महोदय जी, भारत के लाखों लोग अपने घरों को छोड़ कर विदेशों में जा कर रहे और वसुधैव ही कुटुम्बकम में आस्था रख कर और, संसार में रहो और रहने दो, जीयो और जीने दो के आधार पर सैकड़ों मुल्कों में जा कर उन देशों की उन्नति की और खुशहाल बनाया। जहां पर कारखाने नहीं थे वहां कारखाने खड़े किये, जहां पर शिक्षा के लिए प्रोफ़ेसर नहीं थ, इंजीनियर नहीं थे, डाक्टर नहीं थे वहां इन व्यक्तियों में दक्षता रखने वाले भारतीयों ने जा कर उन देशों की तस्वीर को बदला और उनकी अनेक सेवायें कीं। लेकिन इतना करने के बाद भी बर्मा से भारतीय. निकाले गये, कीनिया, उगाण्डा से भारतियों को निकाला गया और 1969 में मलेशिया में इसी तरह की समस्या खड़ी हुई थी, और श्री लंका में यह सिलसिला जारी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने घरों को छोड़ कर दूसरे देशों को आबाद किया, उन देशों में रहने के बाद, वहां के नागरिक बनने के बाद और पचासों साल रहने के बाद वहां से उन को निकाला जा रहा है, लेकिन भारत सरकार के जो मंत्रीगण हैं या हमारी सरकारी एजेन्सीज हैं, उन समस्याओं को विश्व में क्यों नहीं उठातीं कि भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है, उन को खामख्वाह निकाला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो फ़ोरम है उस में इस समस्या को क्यों नहीं उठाया गया, यह मैं जानना चाहता हूं? इस समस्या के बारे में जो सरकारी उदासीनता है वह बहुत ही खेदजनक है। आखिर लाखों की तादाद में भारतीय लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं उन को भी निकालने का सिलसिला जारी होगा, आज बहुत से ऐसे देश हैं जैसे ईराक, अफ़ग़ानिस्तान, कनाडा, इंडोनेशिया और पचासों ऐसे मुल्क हैं जहां पर हजारों की तादाद में भारतीय नागरिक रहते हैं, उन के बारे में भी यह समस्या कभी न कभी खड़ी होने वाली हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए पहले से ही भारत सरकार क्यों नहीं कोई

योजना बनाती जिस से भारतीयों के सामने यह मुसीबत खड़ी न हो। आज दुनिया के देशों में दूसरे देशों के लोगों को निकालने की भावना पैदा हो गई है, तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वह बात श्री लंका तक ही नहीं रहेगी और जो दूसरे देश हैं जहां भारत के लोग बसे हुए हैं, वहां भी यह समस्या खडी होनी है। इसलिए सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस तरह की उदासीनता की नीति छोड़ कर के इस समस्या को सही रूप में समझे और जितने हमारे संसार में फ़ोरम हैं उन में इस बारे में आवाज उठाये।

मैं जानना चाहता हूं कि भारत और श्री लंका के बीच जो समझौता हुआ उस को कार्यान्वित करने के लिए जो बातचीत हुई थी उस में भारत ने क्या क्या मुद्दे रख थे और उन पर श्री लंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आप को मालूम है कि श्री लंका में जो उन को नागरिकता देने का काम था वह बहुत धीरे चल रहा है, और श्री लंका के जो निवासी हैं उन्होंने एसे तरीके और प्रयत्न अपना रखे हैं जिस से कि भारत के लोगों को नागरिकता न मिले और वहां से घबरा कर भारतीय मूलक लोग भाग खड़े हों। समझौते के अनुसार श्री लंका सरकार ने जितने भारतीय लोगों को नागरिकता देने का काम अपने जिम्मे लिया था, मैं जानना चाहता हूं कि उस में कितनी प्रगति हुई, और कितने लोगों को नागरिकता दे दी गई और कितने लोग बाकी हैं? और जिन को नागरिकता नहीं दी गई उस के क्या कारण हैं? साथ ही मैं भी जानना चाहता हूं कि जो लोग श्री लंका से भारत लौट रहे हैं उन की सम्पत्ति का क्या जायजा है, कितने रुपयों की सम्पति लोग वहां छोड़ कर आ रहे हैं? उसके सिलसिले में सरकार क्या कोई कम्पेन्सेशन की बात या उन के रुपये के पेमेन्ट का प्रस्ताव श्री लंका सरकार के सामने रख रही है। क्या भारत सरकार ने ऐसी बात भी पेश की? जो 1964 में समझौता हुआ था उस को रिवाइज करने के लिए कोई सुझाव भारत सरकार ने रखा था?

इस सिलसिले में मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि कुछ मेरे दोस्तों ने जो संसद् सदस्य भी हैं, बतलाया है कि जो लोग लंका से भारत आ रहे हैं उन को रेलवे कस्टम्स पर जो भारत सरकार के कर्मचारीगण हैं वह बुरी तरह से परेशान करते हैं। इस समस्या के बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह क्या करने जा रहे हैं और क्या जल्दी ही सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिससे उपरोक्त विभागों के कर्मचारी गण श्रीलंका से आने वाले लोगों को अकारण ही परेशान न करें?

SHRI SWARAN SINGH; None of these persons who are involved in this Agreement is a citizen of Ceylon. No Sri Lanka citizen is being affected by this Agreement.. This Agreement relates to those persons who for historical reasons happen to be Stateless and there is this Agreement solemnly entered into between two sides in 1964 and both sides have reiterated from time to time that this Agreement will be implemented

About the rate of grant of citizenship by Sri Lanka Government, I have given in the main statement the figures of persons whom citizenship has been granted. If their number is compared to the number of persons repatriated to India, I cannot say that the progress of grant of

citizen-ship by Sri Lanka is slow. The comparison of the two figures will indicate that they are almost in the same proportion as the ultimate picture that is likely to emerge when the Agreement is implemented.

About the assets, there was a clause in the Agreement according to which upto a certain level, the entire assets were to be repatriated and the Government of Sri Lanka had agreed to give the value of those assets in free foreign exchange. There is an exchange ceiling of Rs. 75,000 and the rest can remain in the accounts of these persons in Sri Lanka.

No revised proposals were put forward in the course of these talks. But I have said now in the statement that we are prepared to revise upwards the rate of repatriation to India so that some of the back-log that has been created may be liquidated.

I am sorry to learn if these persons who have been repatriated have faced difficulties in the Customs or at the hands of the Railway authorities. We will issue appropriate instructions—we have already done so—to these authorities so that they are not inconvenienced on that score. The rest of the points raised by the hon. Member were of a general nature which do not relate to the present subject-matter of the Call Attention Notice.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने एक बात कही है कि कुछ कार्य करने में हमसे विलम्ब हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से काम हैं जिनमें विलम्ब हुआ है और इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई हैं ?

श्रीलंका काफी दिनों से इस बात का दावा कर रहा है कि कच्चा तिवू उसका है, और हमारी सरकार कहती है कि हमारा है। वहां से भी काफी लोग भगाये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार का साफ मत क्या है ? उनका है या हमारा है ? यदि हमारा है तो वह दावा क्यों कर रहे हैं, इस बात का खुलासा होना चाहिये।

जो हमारा श्रीलंका के साथ समझौता हुआ था उसके अनुसार 5 लाख 25 हजार लोग यहां आने थे। अब उसमें भी डेढ़ लाख अधिक लोग उनकी भेजने की योजना है। अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बतलाया कि यह राज्य-विहीन लोग हैं। वह न उनके राज्य के हैं न हमारे राज्य के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग वहां से आ रहे हैं वह कितने वर्षों से श्रीलंका में रह रहे थे। यदि वे राज्य-विहीन लोग हैं तो क्या सभी राज्य-विहीन लोगों का हमने ठेका ले रखा है ? यहां एक बात साफ है कि यदि वे हमारे देश के हैं तो विशेष रूप से तमिलनाडु के हैं। चूंकि तमिलनाडु के हैं इसलिये उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको रोकने के लिये सरकार कोई विशेष व्यवस्था करने जा रही है ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सीमा रखी गयी है कि 70 हजार रुपये की सम्पत्ति ला सकते हैं, यह ठीक नहीं है। यह बात कही जरूर गयी है लेकिन श्रीलंका सरकार इसको अमल में नहीं ला रही है। वह लोग बहुत कम सम्पत्ति ले कर आ रहे हैं और यहां आने के बाद उनको सरकार के आश्रय में पड़ा रहना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई पहल करेगी ताकि उनकी जितनी सम्पत्ति है उस पूरी सम्पत्ति को ले कर वह आ सकें ?

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि लोगों की सम्पत्ति उनके नाम से जमा रहेगी। क्या उसका ब्याज मिलेगा या उसके बिना

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

लंका सरकार रखे रहेगी ? यदि लंका सिहरक उसका इस्तेमाल करेगी तो क्या उसारका कोई मुनाफा लोगों को मिलेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि कितने दिनों तक लंका सरकार उसको रख सकती है ? क्या उस सम्पत्ति के वहां रहने पर इसकी आशंका नहीं है कि अभी लंका सरकार उसको जमा रखे और बाद में हड़प ले ? जो भी सम्पत्ति वह लोग ला रहे हैं उसके बारे में श्रीलंका सरकार से आपकी साफ बात होनी चाहिये और आपको जोर देना चाहिये कि वह पूरी सम्पत्ति ला सकें ।

SHRI SWARAN SINGH; Sir, the delay in the implementation of the agreement in accordance with the original understanding was due to legislative and administrative measure that had to be undertaken. In between, there was change of Government in Sri Lanka and the appropriate legislation to implement the provisions was delayed. There were certain other administrative details for which we should not try to put the blame on one side or the other. But there was delay, and that is an accepted fact.

The question about Kachhattivu has nothing to do with the question of Stateless persons, and I think I will be with in my right in saying that that has got no connection with the present call-attention notice.

It is true that these persons who are of Indian origin have been living there for quite some time. Out of these persons who were originally living and who had not been granted citizenship right, some of them had qualified for grant of citizenship and citizenship was granted to those persons. There was dispute about these people which had been pending between the two Governments for a long time, and the two Prime Minister got together and arrived at a settlement which, I think, was in the best interests of both the countries and in the interest of those persons who were involved. Therefore, it will not serve any practical purpose or object now to criticise the agreement which was entered into about nine years back.

Regarding the assets, the agreement is clear about the assets and it is not a matter which could be or should be reopened. There should be some sanctity about international agreements and we should take the agreement as a whole and not try to have objections with one or the other provision of the agreement.

These are all the points.

**श्री हुकम चन्द कछवाय**: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

**अध्यक्ष महोदय** : आपके प्रश्न का कभी उत्तर आया भी है ?

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : जब उत्तर नहीं आया तब मैं क्या करूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह आदत बहुत बुरी है ।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : कच्चा तिवू के बारे में लंका सरकार कह रही है कि वह उनका है और हम कहते हैं कि यह हमारा है । मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है । मंत्री महोदय को इस बारे में साफ उत्तर देना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न तो रिपिटिएशन का । अगर आप इस आइलैण्ड के स्टेटस के बारे में कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो इससे कन्फ्यूजन हो जायेगा । आप इसको रिपैट्रिएशन से मत जोड़िये । इसमें और चीजें इन्वाल्व्ड हैं ।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : मेरी प्रार्थना है कि अगर यह हमा" " तो हमको हिम्मत

के साथ कहना चाहिये। यह सरकार क्यों नहीं कहती ? 70,000 रुपये की जो सीमा बांधी गयी है उसके बारे में मेरा कहना है कि बाकी सम्पत्ति उनके नाम पर जमा रहेगी इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि वह कब तक जमा रहेगी ? उस पर कोई ब्याज मिलेगा या नहीं और कब तक उसको लाया जा सकता है ?

SHRI SWARAN SINGH: This is a matter of detail. If the hon. Member is interested, he can write to me and I will give him all the information.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): On a point of order, Sir. I think the Minister is misleading the House that they are implementing. Actually, he is misleading in the sense that the Indian High Commissioner has closed the register for enrolment of citizens. More than one and a half lakhs of people who are illiterate are not being enrolled.

MR. SPEAKER; There is no point of order.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दें। सत्तर हजार की सम्पत्ति ला सकते हैं। बाकी उनके नाम पर वहां जमा रहेगी। उस पर ब्याज मिलेगा ? कितने समय के बाद उसको वे ला सकेंगे ?

SHRI SWARAN SINGH: I have said that I have not got the details with me. If he is interested, I will find out and inform him.

अध्यक्ष महोदय : आप उनको लिख भेजें। उनके हाथ में कोई चीज होगी तो वे पूछ सकेंगे कि बताओ, मैम्बर पूछते हैं।

MR. CHANDRAPPAN—not here. Normally, he is present. Mr. Atal Bihari Vajpayee—also not here.

MR. SPEAKER: Papers to be laid..

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: (Begusarai); It is your pleasure to give your opinion with regard to the submission I made the other day?

अध्यक्ष महोदय लास्ट डे को आने दिया था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उनको फुल वर्किंग डे मिल गया था ?

With regard to privilege, is there no sense of urgency or priority?

MR. SPEAKER; The question of privilege is not there. You were allowed only to refer to this matter...

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम तो समझते हैं। कम से कम पच्चीस मैम्बर के यहां खड़ा होने की हालत हैं।

MR. SPEAKER; Let the Minister make a statement.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I must assert, Sir, that the Ministers cannot be allowed to go on till the end of the year. We have got a certain amount of urgency in the matter. We cannot allow them to go on like this. Here is a *prima facie* case that we have been misled by the two Ministers. It is these who have made a wilful misrepresentation. They have to be taken to task by the House.

We want to know the reasonable time that you want to grant them.

अध्यक्ष महोदय डायरेक्शन 115 के बजाय स्टेटमेंट करने की इजाजत दे दी थी। कमेंट मांगे हैं जब आ जाएंगे बता देंगे।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: The more they prevaricate, the more they misrepresent, they will get into further trouble. Even God cannot save them...God cannot save them if they further misrepresent.

Let the Chair allow them a reasonable time within which the Minister should be expected to give a reply.

MR. SPEAKER; I think they must come very soon. They will come at the earliest.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Will the Minister for Parliamentary Affairs indicate the time, Sir? He is here. Now, we are flooded....

MR. SPEAKER; Mr. Raghu Ramaiah, when will that come?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): The Government are going through the material. They will submit their comments to you, I think, by tomorrow.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: By tomorrow?

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: To the Speaker. They will be submitted to the Hon'ble Speaker.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour); Last session, when I threw a piece of burnt paper here, a privilege motion was adopted within half an hour, although there was no case for a privilege motion. But, in this case, there is so much delay. Is it because it concerns the Prime Minister and her son?

I have given a notice with regard to the arrest of Jagota brothers and their sister. They have been refused bail. They are peculiar people. We want the Home Minister to make a statement.

MR. SPEAKER: I am sorry, I cannot allow it. It is a matter already in the Court. It is *sub-judice*.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am not allowing it.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It is already before the Court.

Now, Papers to be laid on the Table. Shri Shinde.

---

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**12.26 hrs.**

STATEMENT SHOWING REASONS FOR DELAY IN LAYING REPORT OF WEST BENGAL AGRO-INDUSTRIES CORPORATION, LTD. CALCUTTA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): I beg to lay on the Table a statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Annual Report of the West Bengal Agro-Industries Corporation Limited, Calcutta, for the year 1969-70. [*Placed in Library. See* No. LT-4257/73.]

NOTIFICATION UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: On behalf of Prof. Shri Singh, I beg to lay on the Table a copy of the Sugar (Price Determination for 1972-73 Production) Amendment Order, 1972 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 38(E) in Gazette of India dated the 30th January, 1973, under sub-section (6) section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See* No. LT-4258/73].

ARCHITECTS (EXPERT COMMITTEE) RULES, 1972, INDIAN MUSEUM (AMENDMENT) RULES, 1972, AND NOTIFICATION UNDER VICTORIA MEMORIAL ACT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): I beg to lay on the Table—

(1) (i) A copy of the Architects (Expert Committee) Rules, 1972 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 1208 in Gazette of India dated the 30th September, 1972, under